



जहां कहीं पसीना नगीना बना हुआ है, वहीं रहना चाहता हूँ

विद्रोह के साथ बात यह है कि आज जो विद्रोह है, वह कल की समाज-रचना करत है और परसों रूढ़ि हो जाता है। बौद्ध और जैन धर्म भी तत्कालीन समाज-रचना के खिलाफ विद्रोह थे। समाज में रूढ़ि बन जाती है। गद्दियां स्थापित हो जाती हैं। आधुनिक लोकतंत्र में राजनेताओं को जब गद्दियां बन जाएंगी, तब इनके खिलाफ भी विद्रोह होगा। लोग साहित्य को जीवन से भिन्न मानते हैं, वे कहते हैं कि साहित्य अपने ही लिए हो। साहित्य का यह धंधा नहीं कि हमेशा मधुर ध्वनि ही निकाला करे। जीवन को हम एक रामायण मान लें। रामायण जीवन के प्रारंभ का मनोरम बालकांड ही नहीं, किंतु करुण रस में औत्प्रेयित अरण्यकांड भी है और धधकती हुई



पुद्गालि से प्रज्वलित लंकाकांड भी है। जहां कहीं मनुष्य का अपने अभिमत के प्रति समर्पण है, जहां कहीं जीवन की श्रम से आराधना है, जहां कहीं उत्सर्ग और बलिदान के मोमदीप अंधकार को अपनी बलि दे रहे हैं, जहां कहीं नगण्यता गण्यमान्यता को चुनौती दे रही है, जहां कहीं हिमालय की रक्षा में सिरों के शशधरियों पर लेकर मरण-त्यूहार मनानेवाली जवानियां हैं और जहां कहीं पसीना नगीना बना हुआ है, वहीं पर, केवल वहीं पर, आपका माखनलाल दिखते हुए या न दिखते हुए भी उपस्थित रहना चाहता है।

साहित्य के नाते देश की अन्य भाषाओं से अधिक संरक्षण हिंदी अपने लिए नहीं मांग सकती। किंतु राष्ट्रभाषा के शिक्षण, संवर्धन और उत्तरदायित्वों का उचित ज्ञान देश के सामने रखा जाए, तो इस देश की देशभक्ति अपने देश को राष्ट्रभाषा को कभी अरक्षणोय छोड़ देने के लिए प्रस्तुत न होगी। किंतु यह तब तक न होगा, जब तक हम राष्ट्रभाषा के सांगोपांग अध्यापन, दिशादर्शन और उसके उत्तरदायित्वों की मीमांसा का प्रबंध इस देश के विश्वविद्यालयों द्वारा नहीं होने देंगे।

-दिवंगत हिंदी कवि

विककी, प्रोफेसर और वह लड़का

विककी नामक एक लड़के की कथा, जिसे एक मामूली दुर्घटना ने चुनौती का एहसास कराया।



प्रोफेसर विककी को समझा रहे थे, बेटा, अभी तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ देखना है। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, पर तुम्हें हर काम बहुत संभल कर करना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि जो दूसरों के साथ हुआ है, वह तुम्हारे साथ कभी न हो। यानी चुनौतियां किसी के भी सामने आ सकती हैं। इसलिए हमें हर चुनौती से लड़ने की तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए। विककी प्रोफेसर को धन्यवाद देते हुए वहां से चला गया। उसने लगे, प्रोफेसरों का यही काम होता है। बेकार में हमें डराते रहते हैं। यह सोचते-सोचते वह कॉलेज की सीढ़ियां उतरने लगा।

अचानक उसने देखा कि सामने से एक लड़का बैसाखियों की मदद से उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था। उस लड़के को देखकर वह सोचने लगा, इसके लिए सीढ़ियां चढ़ना कितना मुश्किल होता होगा। उसे हर कदम पर बहुत संभल कर चलना पड़ता होगा। ऐसे लोगों को प्रोफेसर की जरूरत है, जो उसे विपत्तियों से बचने और चुनौतियों का सामने करने का रास्ता बता सकें। अभी विककी यह सब सोच ही रहा था कि उसका पैर सीढ़ी से फिसलता, लेकिन उस बैसाखी वाले लड़के ने उसे पकड़कर गिरने से बचा लिया और पूछा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? विककी हैरान था। बैसाखी वाला लड़का बोला, दरअसल वहां एक सीढ़ी थोड़ी टेढ़ी है, जिससे पैर फिसल जाता है। पिछले साल मैं भी वहां से फिसल गया था। शुक है, तुम्हें चोट नहीं आई। संभलकर चला करो। वह चला गया, पर विककी स्तब्ध रह गया। उसे यह एहसास हुआ कि वह जो भी करता है, उसे बहुत सोच-समझ कर करना चाहिए, पूरे ध्यान, लगन और मन के साथ। जैसा कि प्रोफेसर ने उसे कहा था कि हर चुनौती से लड़ने की तैयारी रखनी चाहिए। यह जरूरी नहीं कि जो दूसरों के साथ हुआ, वह हमारे साथ कभी न होगा।

हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए, चुनौतियां बताकर नहीं आतीं।

कांग्रेस घोषणा पत्र के जरिये मतदाताओं के व्यापक वर्ग तक पहुंचना चाहती है, जो उससे लगातार दूर होते गए हैं। मगर वह 'न्याय और जीडीपी का छह फीसदी शिक्षा पर खर्च करने जैसे वादों को चुनावी विमर्श के केंद्र में कैसे लाती है, यह एक बड़ी चुनौती है।

कैसे निभाएंगे

राजनीतिक

पाटियां अक्सर चुनावी घोषणा पत्रों के आधार पर न तो चुनाव लड़ती हैं और न ही उनमें किए गए वादों के प्रति जवाबदेही स्वीकार करती हैं। इसके बावजूद कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को जैसा व्यापक रूप दिया है, उससे साफ है कि उसके भीतर काफी उथल-पुथल है और वह अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस घोषणा पत्र के जरिये मतदाताओं के व्यापक वर्ग तक पहुंचना चाहती है, जो उससे लगातार दूर होते गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही सबसे गरीब पांच करोड़ परिवारों को सालाना 72 हजार रुपये देने वाली न्यूनतम आय योजना यानी 'न्याय' को मोदी सरकार के

खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मगर दूसरी ओर पार्टी वित्तीय घाटे को तीन फीसदी पर लाने की बात भी करती है, जिसे हासिल करना कठिन होगा। अलबत्ता शिक्षा के मद में जीडीपी का छह फीसदी देने और अलग से किसान बजट पेश करने का वादा बहुत ही साहसिक है। कांग्रेस ने अपने पिछले घोषणा पत्र में भी लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का वादा किया था, लेकिन अच्छा तो यह होता कि वह ममतता बननी और नवीन पटनायक की तरह अधिक से अधिक महिलाओं को उम्मीदवार बनाती! पार्टी ने सत्ता में आने पर मार्च, 2020 तक 22 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा किया है, यह रोजगार के मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए अहम है, जिसमें वह मोदी सरकार पर

सालाना दो करोड़ नौकरियां देने के वादे पर अमल न करने का आरोप लगाती आई है। उसने जीएसटी में भी बदलाव करने का वादा किया है, जिसकी व्यावहारिकता पर सवाल उठाए जा सकते हैं। मगर ऐसे दौर में जब पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले और फिर बालाकोट में आतंकी शिविर पर की गई कार्रवाई के बाद जब भाजपा ने राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनावी मुद्दा बना दिया है, देशद्रोह से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए को खत्म करने और विवादित अफसा (सशस्त्रकल विशेषाधिकार अधिनियम) में संशोधन करने का वादा कर कांग्रेस ने उसे अपने खिलाफ एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। अभी कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह कैसे अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को चुनावी विमर्श के केंद्र में लाती है।

कितना कारगर होगा विकास का मुद्दा



इस बार चुनाव में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के मतदाताओं को एकजुट करने वाला कोई एक मुद्दा नहीं है। कुछ मुद्दे हैं, जो देश के कुछ हिस्सों में हावी रहेंगे, तो देश के शेष अन्य हिस्सों में उनकी कोई खास चर्चा नहीं होगी। कोई नहीं जानता कि आखिरकार क्या होगा, इसलिए मैं किसी भी तरह की भविष्यवाणी करने के खेल में नहीं पड़ूंगी। इसके बजाय, मैं अपनी हाल की हरियाणा राज्य के कुछ इलाकों की यात्रा से संबंधित संस्मरण आपके साथ साझा करना चाहती हूँ।

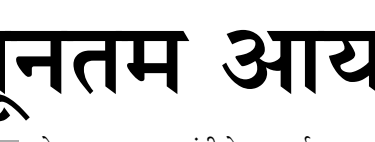
पिछले हफ्ते मैं मेवात गई, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा का एक जिला है। दो साल पहले इसका नाम बदलकर नूंह कर दिया गया है। नीति आयोग के 101 सबसे पिछड़े जिलों की सूची में नूंह सबसे निचले पायदान पर है। इन पिछड़े जिलों को अब आंकांशी जिला कहा जाने लगा है। दिल्ली से मात्र दस घंटे का सफर करके आप नूंह जा सकते हैं और यह मॉल, मल्टीप्लेक्स तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शहर गुरग्राम से सीमाएं साझा करता है। मुस्लिम बहुल नूंह गुरग्राम लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है,

जिसका प्रतिनिधित्व इस समय भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह कर रहे हैं।

क्या नूंह में विकास हुआ है? जैसा कि हर मामले में इस ध्रुवीकृत समय में हो रहा है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रश्न किससे पूछा जा रहा है। कुछ चीजें वाकई नूंह में बदली हैं। वर्ष 2016 में हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा एक आकर्षक बस स्टैंड का उद्घाटन किया गया था। यह एक सुलभ शौचालय और रात्रि विश्रामालय

से सुसज्जित है, जहां पचास रुपये देकर आप रात गुजार सकते हैं। रात्रि विश्रामालय की देखभाल करने वाला खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करता रहा था और वह मानता है कि वह न केवल मजबूत नेता हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, बल्कि वह विकास के भी 'मसीह' हैं।

मैंने उससे नूंह के ग्रामीण इलाके के पिछड़े तबकों और मुस्लिम आबादी की भावनाओं के



पत्रलेखा चर्चार्थी, वरिष्ठ पत्रकार



मंजिलें और भी हैं
>> संदीप तांबे

स्थानीय लोगों के सहयोग से वनों की बर्बादी रोकी

हमारा पैतृक गांव नकवाल मध्य प्रदेश के मंडला जिले में नर्मदा किनारे बसा हुआ है। चारों ओर सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। दूर तक फैले खेत हैं। हम बचपन में अक्सर छुट्टियां बिताने के लिए वहां जाया करते थे। गांव के आसपास गोंड और बैगा आदिवासियों की बस्तियां हैं। मैं अक्सर इन जनजातियों के बच्चों के साथ खेला करता था। इस परिवेश ने प्रकृति के प्रति कैसे गहरा जुड़ाव पैदा कर दिया, पता ही नहीं चला। तब तो मुझे एहसास भी नहीं था कि बड़ा होकर मैं भारतीय वन सेवा के अधिकारी के रूप में काम करूंगा। मेरे जीवन का बड़ा हिस्सा तो राऊरकेला और भिलाई जैसी जगहों में बीता, जहां स्टील संयंत्रों में मेरे पिता काम करते थे। वह भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) के अधिकारी थे। 1990 में मेरा चयन आईआईटी बॉम्बे में हो गया, जहां से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। पर्वट स्थित आईआईटी परिवार भी प्राकृतिक रूप से समृद्ध है। यह बोवली नेशनल पार्क के नजदीक स्थित है। उन्हीं दिनों मैं वाइल्डलाइफ क्लब से जुड़ा और मुझे पश्चिमी घाट, मुदुमलाई नेशनल पार्क, राणथंभौर टाइगर रिजर्व जाने का अवसर मिला, जिससे मुझे प्रकृति का और करीब से जानने का मौका मिला। यही वह समय था, जब मैंने तय किया कि मैं प्रकृति के संरक्षण की दिशा में ही करियर बनाऊंगा। हालांकि यह आसान नहीं था। खासतौर से अपने माता-पिता को राजी करना, क्योंकि आईआईटी में पढ़ रहे अपने बेटे से उन्हें कोई और उम्मीद थी। तीन वर्ष तक इन्फोसिस में काम करने के बाद मैंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की और फिर भारतीय वन सेवा से जुड़ गया। दो वर्ष तक देहरादून स्थित नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में प्रशिक्षण के बाद मुझे सिविकल कैडर मिला। मैं तब इस राज्य के बारे में बहुत कम जानता था। शुरुआत में मुझे साऊथ सिविकल और वेस्ट सिविकल जिलों का प्रभार मिला था, वहां वनों का संरक्षण बड़ी चुनौती थी। पर्याप्त ढांचा नहीं था, शिकारियों से वन्यजीवों को बड़ा खतरा था और वन संरक्षण कानून पर अमल चुनौती थी। स्थानीय लोग वनों पर ही निर्भर थे। वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी। व्यवस्थित चारागाह नहीं होने के कारण वे अपने मवेशियों को खुला छोड़ देते थे। इन सबका बुरा असर वहां जैव-पारिस्थितिकी पर पड़ रहा था। मुश्किल यह थी कि हमारे सिर्फ दस फॉरेस्ट गार्ड और कुछ अधिकारी भर थे। वनों को बचाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता था और वह यह कि इससे स्थानीय समुदाय को जोड़ा जाए। हमने ग्रामीणों के बीच अभियान चलाया और उन्हें बताया कि कैसे अत्यवस्थित पशुपालन का नुकसान वनों को होता है। हमने इको डेवलपमेंट कमटी बनाई और उसे वनों को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई करने का अधिकार दिया, जिससे उनमें वनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। वन्यजीव विभाग और स्थानीय लोगों के दोहरे दबाव के कारण अर्ध-बेरोजगारी भी काम किया गया। इसके लिए ग्राम सभा को विधायक से लेकर पोखरी संरक्षण समिति (पीएसएस) बनाई गई। पीएसएस झील देखने आने वाले पर्यटकों से दस रुपये लेती है। इसका सकांतात्मक प्रभाव पड़ा। ऐसी छोटी-छोटी पहल बताती है कि स्थानीय लोगों को जोड़कर प्रकृति की खूबसूरती को बचाया जा सकता है।



हमने गांव वालों को समझाया कि कैसे अत्यवस्थित पशुपालन का नुकसान वनों को होता है।

निर्मित साक्षात्कार पर आधारित

न्यूनतम आय योजना आदर्श होगी?

इसका क्या भरोसा है कि न्यूनतम आय योजना का लाभ गलत हाथों में नहीं जाएगा, आखिर करोड़ों की तादाद में फर्जी राशन कार्ड भी तो पकड़े गए हैं, जिनका जिन्न

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 25 मार्च को घोषणा की थी कि कांग्रेस की सरकार बनी, तो देश का कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा, जिस की न्यूनतम आय 12 हजार रुपये से कम हो। जिस परिवार की आय इससे कम होगी, उसकी 6000 रुपये तक की भरपाई सरकार करेगी। हालांकि अगले दिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने इसे दुरुस्त करते हुए बताया कि यह भरपाई योजना नहीं होगी, अलबत्ता पांच करोड़ गरीब परिवारों को 6,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी न्यूनतम 12 हजार रुपये आमदनी और भरपाई का जिक्र नहीं है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की खिल्ली उड़ते हुए कहा कि एनडीए सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इससे ज्यादा राहत तो पहले ही दे रही है।

यह ऐसी योजना नहीं है, जिस पर पहले कहीं विचार नहीं किया गया हो। इन्साइल जैसे कुछ देशों में यह योजना नेगेटिव आय के रूप में लागू है। इस तरह की योजना में एक व्यक्ति की न्यूनतम आय तय कर दी जाती है, उससे ऊपर की आमदनी पर टैक्स लगता है, और जिसकी आमदनी उससे कम होती है, उसे बाकी राशि की भरपाई की जाती है। राष्ट्रपति निक्सन ने नेगेटिव आयकर योजना को अमेरिका में लागू करने का प्रस्ताव रखा था, पर अमेरिकी कांग्रेस से इसकी मंजूरी नहीं दी। अलबत्ता बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए योजना लागू की गई, जिसे स्पल्लेन्ट सेवयोरिटी नाम दिया गया।

न्यूनतम आय योजना अर्ध-बेरोजगारी भत्ते की तरह है। कांग्रेस के घोषणा पत्र ने भी इस पर विस्तार से प्रकाश नहीं डाला है। हालांकि यह जरूर कहा गया है



अजय सेतिया

कि शुरू में जीडीपी का एक प्रतिशत खर्च होगा और बाद में दो प्रतिशत तक खर्च होगा, जिसे अन्य संसाधनों से इकट्ठा किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि विशिष्ट उद्देश्यों वाली सब्सिडी बंद नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि एक-दो तरह की सब्सिडी को छोड़कर सब्सिडी की बाकी सभी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी।

राहुल गांधी ने 6,000 रुपये न्यूनतम आय की जरूरत किस आधार पर तय की है, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। क्या पांच सदस्यों के एक परिवार के लिए छह हजार रुपये घर चलाने के लिए काफी हैं? महानगरों में एक कमरे का मकान छह हजार रुपये तो क्या 12 हजार रुपये किराये पर भी नहीं मिलता। किसी

खुली खिड़की

भारत समेत दुनिया भर में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2014 में जहां 1.57 अरब लोग स्मार्टफोन का उपयोग करते थे, वहीं अब ऐसे लोगों की संख्या बढ़कर 2.71 अरब हो गई है। एक अप्रैल, 2019 को दुनिया की आबादी 7.7 अरब थी।

आसक्ति से पतन

आचार्य तुलसी कहते थे कि किसी भी तरह की आसक्ति या महत्वाकांक्षा से सर्वथा मुक्त रहने में ही कल्याण है। एक दिन उन्होंने एक कथा सुनाई-एक महत्त्वा की घोर तपस्या से उनके आश्रम में सिंह और बकरी, सर्प और मेंढक तक वैभ-भुवा भुलाकर प्रेम के साथ रहने लगे। इंद्र को लगा कि यदि महात्मा की तपस्या चलती रही, तो उनका आसन अधिक दिन टिक नहीं पाएगा।

उन्होंने महात्मा को तपस्या से डिगाने का निश्चय किया। वेश बदलकर वह महात्मा के आश्रम पहुंच गए और महात्मा से कहा, महाराज, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। यह तलवार आपके पास छोड़ें जा रहा हूँ। यदि इसका ध्यान रख सकें, तो आभारी रहूंगा। संत ने स्वीकृति दे दी। महीनों बीतने के बाद भी इंद्र तलवार लेने आश्रम नहीं आए। महात्मा जी ने सोचा कि तलवार किसी की धरोहर है, इसलिए उसे अपने पास रखने लगे। जहां जाते तलवार साथ ले जाते, ताकि कोई उसे चुरा न ले। भगवान में हर समय लीन रहने वाला मन अक्सर तलवार की ओर चला जाता। इस तरह संत की साधना का क्रम भंग होने लगा। साधना में विघ्न पड़ने से आश्रम का सौत्तिक वातावरण दूषित होने लगा और जो जीव हिंसा त्याग कर मैत्री भाव से साथ-साथ रहते थे, वे फिर एक दूसरे का भक्षण करने लगे। यह कहानी सुनाकर आचार्य तुलसी कहते थे-किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति जीवन भर की तपस्या को पल भर में नष्ट कर देती है।



सत्संग

